

- यह नरिदेश हाल ही में **सरवोच्च न्यायालय** के उस **नरिणय** के बाद दया गया है, जसमें [११११११११ १११११ ११११ ११११११११ ११ १११११११११ ११११११. 2023](#) में **अनुच्छेद 142** का प्रयोग करते हुए राज्य वधिनसभाओं द्वारा पारति वधियकों पर काररवाई करने के लयि **राज्यपालों** और **राष्ट्रपति** के **समयावधि नरिधारति** की गई थी।
- इस संदरभ में **14 प्रमुख प्रश्नों** पर वचिर करने का नरिदेश दया गया है, जो मुख्य रूप से **अनुच्छेद 200** और **201** से संबंधति हैं तथा वधियक के अधनियम बनने से पहले **कार्यकारी काररवाइयों की न्यायसंगतता से संबंधति हैं**।

President's 14 Questions to Supreme Court

• What are the constitutional options before a Governor when a Bill is presented to him under Article 200? • Is the Governor bound by the aid & advice of the Council of Ministers while exercising the options available with him when a Bill is presented before him? • Is the Governor's constitutional discretion under Article 200 justiciable? • Is Article 361 an absolute bar to the judicial review in relation to the actions of a Governor under Article 200? • In the absence of a constitutionally prescribed time limit, and the manner of exercise of powers by the Governor, can timelines be imposed and the manner of exercise be prescribed through judicial orders? • Is the exercise of constitutional discretion by the President under Article 201 justiciable? • In the absence of a constitutionally	• Are the decisions of the Governor and the President under Article 200 and Article 201, respectively, justiciable at a stage anterior into the law coming into force? Is it permissible for the Courts to undertake judicial adjudication over the contents of a Bill, in any manner, before it becomes law? • Can the exercise of constitutional powers and the orders of/by the President /Governor be substituted in any manner under Article 142? • Is a law made by the State legislature a law in force without the assent of the Governor granted under Article 200? • In view of the provision to Article 145(3), is it not mandatory for any bench of the Supreme Court to first decide whether the question before it involves substantial questions of law as to the interpretation of the Constitution and to refer it to a bench of minimum five Judges?
prescribed timeline and the manner of exercise of powers by the President, can timelines be imposed and the manner of exercise be prescribed through judicial orders? • Is the President required to seek advice of the Supreme Court by way of a reference under Article 143 and take the opinion of the Supreme Court when the Governor reserves a Bill for the President's assent or otherwise?	• Are the powers of the Supreme Court under Article 142 limited to matters of procedural law or Article 142 extends to issuing directions which are contrary to or inconsistent with existing substantive or procedural provisions of the Constitution or law in force? • Does the Constitution bar any other jurisdiction of the Supreme Court to resolve disputes between the Union Government and the State Governments except by way of a suit under Article 131 of the Constitution of India?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 क्या है?

- अनुच्छेद 143 (सलाहकार क्षेत्राधिकार) भारत के राष्ट्रपति को किसी भी कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है, जो सार्वजनिक महत्त्व का है और जिसके उठने की संभावना है या जो पहले ही उठ चुका है।
 - यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को स्थापित करता है, जो केवल राष्ट्रपति के लिये है।
- संदर्भित प्रश्नों के प्रकार:
 - अनुच्छेद 143 (1): राष्ट्रपति किसी भी वधि या तथ्य के प्रश्न को, जो सार्वजनिक महत्त्व का हो या जिसके उठने की संभावना हो, सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या देने से इंकार कर सकता है।
 - उदाहरण के लिये, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1993 में [राम जनमभूमिभामले](#) के संबंध में अपनी राय देने से इंकार कर दिया था।
 - अनुच्छेद 143(2): यह राष्ट्रपति को संविधान-पूर्व किसी भी संधि, समझौते, वचन, सनद या अन्य समान दस्तावेजों से उत्पन्न विवादों को राष्ट्रपति को संदर्भित करने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी राय राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है।
- सलाह की प्रकृति: दोनों मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय केवल परामर्शात्मक है, न कि न्यायिक घोषणा।

- इसलिये, यह राष्ट्रपति के लिये **बाध्यकारी नहीं** है; वह इस राय का पालन भी कर सकता है और नहीं भी।
- हालाँकि, यह सरकार को किसी मामले पर नरिणय लेने हेतु **आधिकारिक कानूनी राय** प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

राष्ट्रपति की शक्त के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह **केंद्रीय मंत्रपरिषद की** सलाह के आधार पर किसी विधिया सार्वजनिक महत्त्व के तथ्य के प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय के लिये प्रेषित कर सकते हैं।
 - अनुच्छेद 145 (3) के अनुसार ऐसे संदर्भों की सुनवाई **कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी**।
- ऐतिहासिक संदर्भ: अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार की उत्पत्ति भारत सरकार अधिनियम, 1935 से हुई है, जिसके अंतर्गत गवर्नर-जनरल को संघीय न्यायालय को कानूनी प्रश्नों के संदर्भ में भेजने की अनुमति थी।
 - **कनाडा का संविधान** अपने सर्वोच्च न्यायालय को कानूनी मत देने की अनुमति देता है, जबकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय शक्ति पृथक्करण की सख्ती बनाये रखने के लिये परामर्शात्मक मत देने से बचता है।
- ऐसे संदर्भों के पछिले उदाहरण: अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा लगभग 15 संदर्भ भेजे गए हैं। कुछ ऐतिहासिक मामले इस प्रकार हैं:
 - **दिल्ली कानून अधिनियम मामला (1951):** इसने प्रतिनिधिक विधायन (Delegated Legislation) की सीमा को परभाषित किया।
 - **केरल शिक्षा विधायक (1958):** नरिदेशक संधिधर्तों के साथ मौलिक अधिकारों का सामंजस्य स्थापित किया।
 - **बेरुबारी मामला (1960):** यह नरिणय दिया गया कि क्षेत्रीय हस्तांतरण के लिये **संवैधानिक संशोधन** आवश्यक है।
 - **केशव सहि केस (1965):** इसने विधायी विशेषाधिकारों की व्याख्या की।
 - **राष्ट्रपति चुनाव मामला (1974):** इसमें कहा गया कि राज्य विधानसभाओं में रक्तियों के बावजूद चुनाव कराए जा सकते हैं।
 - **तृतीय न्यायाधीश मामला (1998):** न्यायिक न्युक्तियों के लिये **कॉलेजियम प्रणाली** की स्थापना की गई।
- वर्तमान संदर्भ में प्रमुख मुद्दे: यह इस बारे में मुद्दा उठाता है कि न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपालों पर समयसीमा लागू कर सकते हैं, जो संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं है (विशेषकर अनुच्छेद 200 एवं 201 के अंतर्गत)।
 - यह अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय प्रावधान) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की सीमा पर भी प्रश्न उठाता है।
- सलाहकार संदर्भ के माध्यम से नरिणय पलटने की शक्ति: वर्ष 1991 के **कावेरी जल विवाद** न्यायाधिकरण के अनुसार, अनुच्छेद 143 का उपयोग स्थापित न्यायिक नरिणयों की समीक्षा करने या उन्हें पलटने के लिये नहीं किया जा सकता है।
 - हालाँकि, सरकार अभी भी 2023 नरिणय को चुनौती देने के लिये समीक्षा या उपचारात्मक याचिकाएँ दायर कर सकती है।

राष्ट्रपति संदर्भ प्रणाली का महत्त्व क्या है?

- भूमिकाओं की संवैधानिक व्याख्या: यह राष्ट्रपति और राज्यपालों की संवैधानिक भूमिकाओं को स्पष्ट कर सकता है तथा यह भी स्पष्ट कर सकता है कि क्या गैर-समयबद्ध कार्यकारी कार्य न्यायिक निगरानी के अधीन हो सकते हैं।
- लोकतांत्रिक ढाँचे की पुनः पुष्टि: यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्त संतुलन को पुनः परभाषित करने का अवसर प्रदान करता है तथा अतिक्रमण को रोककर संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
- प्रक्रियागत निश्चितता: यह अंतर-सरकारी मामलों में प्रक्रियागत अनिश्चितताओं का समाधान करता है और भविष्य में संस्थागत घर्षण को हल करने के लिये दिशानिर्देश स्थापित करने में सहायता प्रदान कर सकता है।
- सुचारू संघीय कार्यप्रणाली: संघीय ढाँचे में, यह संदर्भ केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को परभाषित करने में सहायता प्रदान करता है तथा विवाद समाधान के लिये स्पष्ट कानूनी ढाँचे के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रपति संदर्भ प्रणाली में चुनौतियाँ क्या हैं?

- गैर-बाध्यकारी प्रकृति: सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 143 की सलाह राष्ट्रपति पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, जिससे इसका व्यावहारिक प्रभाव सीमित हो जाता है और इसकी प्रभावशीलता पर संदेह उत्पन्न होता है।
- संभावित राजनीतिकरण: यह प्रणाली राजनीतिक दुरुपयोग के जोखिम से जुड़ी होती है, विशेष रूप से जब सत्तारूढ़ सरकार विवादास्पद नरिणयों को वैध सदिध करने या प्रतिकूल नरिणयों पर प्रश्न उठाने के लिये इसका उपयोग करती है। इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है तथा उसे राजनीतिक विवादों में शामिल किया जा सकता है।
- संदर्भ के लिये अस्पष्ट मानदंड: संविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि "सार्वजनिक महत्त्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर" कसि माना जाएगा। इस कारण कार्यपालिका को अत्यधिक विकास अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिससे कभी-कभी ऐसे मामलों को भी संदर्भित किया जा सकता है जिनका वास्तविक संवैधानिक महत्त्व नहीं होता।
- संस्थागत तनाव: संदर्भ अक्सर न्यायपालिका-कार्यपालिका के विवादों से उत्पन्न होते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है और विशेष रूप से स्थापित नरिणयों की पुनः समीक्षा के समय न्यायिक स्वतंत्रता दुर्बल हो सकती है।
- प्रतिक्रिया के लिये समय-सीमा का अभाव: संविधान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति संदर्भ पर प्रतिक्रिया देने के लिये कोई निश्चित समय-सीमा नरिधारित नहीं की गई है, जिससे आवश्यक मामलों में देरी हो सकती है और शासन तथा नीतिगत स्पष्टता में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

निष्कर्ष

